International Journal of Academic Research and Development
ISSN: 2455-4197, Impact Factor: RJIF 5.22
www.academicsjournal.com
Volume 2; Issue 4; July 2017; Page No. 811-814

कृषि एवं ग्रामीण विकास में सूचना–संचार तकनीक की भूमिका

डॉ0 अरूण प्रताप सिंह

डी0फिल्0, भूगोल विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत।

प्रस्तावना

भारत में जब सूचना–संचार क्रान्ति की शुरूआत हुई थी तो लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह ग्रामीण विकास में भी योगदान देगा, परन्तु आज ग्रामीण इलाके में विकास का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है सूचना–संचार क्रान्ति। वास्तव में सूचना–संचार क्रान्ति के जरिए किसी भी गाँव की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। ग्रामीण विकास में सूचना–संचार तकनीक की महत्ता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब मिट्टी के घरों में भी मोबाइल की घंटियाँ बजती हैं। गाँवों में टेलीफोन और ब्राडबैंड इन्टरनेट के कनेक्शन देने से उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इससे अब गाँव–गाँव बी.पी.ओ. और साइबर कैफे खुल रहे हैं, जिससे शिक्षित ग्रामीण युवाओं को गाँव में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहें हैं और उन्हें शहरों का चक्कर नही काटना पड़ रहा है। दूसरी तरफ इससे ग्रामीण इलाकों में बैकिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा से सम्बन्धित सेवाओं को पहुँचाना आसान हो गया है। इन्टरनेट और ब्राडबैंड की सुविधा ग्राम पंचायत तक पहुँचने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि गाँव के आम आदमी तक सार्वजनिक सेवाओं की पहुँच बहुत आसान हो गई है।

सूचना–संचार क्रान्ति कृषि क्रान्ति की दिशा में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। किसान आज ई–कृषि की तरफ कदम बढ़ा दिये हैं। संचार क्रान्ति से कृषि संबंधित तकनीकी जानकारी किसानों को पहले की अपेक्षा कई गुना बेहतर और समय से मिल रही है। आज भारत का किसान एस0एम0एस0 के जरिए मौसम की जानकारी प्राप्त कर रहा है तो 'किसान कॉल सेन्टर' और 'ई–चौपाल' जैसी सुविधाओं से खेती में होने वाले खतरे कम हो रहे हैं, इससे जहाँ कृषि उत्पादन बढ़ने से किसानों की माली हालत सुधरी है वहीं उनके रहन–सहन के स्तर में भी गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है।

कृषि के साथ–साथ पंचायतों के कामकाज को कारगर और सुचारू बनाने के लिए ई–प्रशासन योजना पर अमल किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत भूमि के रिकार्डों का कम्प्यूटरीकरण, राशनकार्ड, जन्म–मृत्यु प्रमाणपत्र तथा इसी तरह के अन्य रोजमर्रा के काम ई–प्रशासन के जरिए किये जा रहे हैं। गाँवों में संचार सुविधाओं के विकास के साथ ही सरकारी सुविधाओं का भी विकास हुआ है। जिन गाँवों में इन्टरनेट की सुविधा है वहाँ किसी भी तरह की समस्या हो, तुरन्त इंटरनेट के जरिये इसकी सूचना जिला प्रशासन एवं सचिवालय तक पहुँचा दी जाती है।

संपेक्ष में सूचना–संचार तकनीक भारत के ग्रामीण इलाकों के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आज यह तकनीक प्रशासन, बैंकिंग, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, समाजसेवा जैसे सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है इससे काम तो जल्दी और सुगमता से होता है साथ में पारदर्शिता भी बनी रहती है, जिससे भ्रष्टाचार और हेराफेरी पर काबू पाने में भी मदद मिलती है। फिलहाल एक सच्चाई यह भी है कि जिस गति से सूचना–संचार तकनीक का विकास हो रहा है उसी गति से विकास के दूसरे पहलुओं को भी तेज करने की जरूरत है। साथ ही साक्षरता दर का बढ़ना भी एक और बुनियादी जरूरत है जो अपेक्षित बदलावों को तेजी से अमल में लाने की जरूरी शर्त है।

हमारे आसपास की दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। इसका अहसास हमें तब होता है जब हम किसी गाँव में जाते हैं। आज ग्रामीण इलाके में विकास का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है 'सूचना–संचार क्रान्ति। वास्तव में संचार क्रान्ति के जरिए किसी भी गाँव की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। ग्रामीण विकास में सूचना–संचार तकनीक की महत्ता का अन्दाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब मिट्टी के घरों में भी मोबाइल की घंटियां बजती हैं।

सूचना–संचार तकनीक ने सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचने की रफ्तार को अत्यन्त तीव्र करके लोगों की पहुँच को बहुत व्यापक बना दिया है और इससे ग्रामीण विकास की रफ्तार तीव्र हुई है। मोबाइल ग्रामीण इलाके में किसानों को खूब फायदा पहुँचा रहा है। किसानों को उत्पादन खर्च कम करने और उपज की अच्छी कीमत हासिल करने में मोबाइल फोन ने खासतौर पर मदद की है। खेती के दौरान तीन ऐसी अवस्थाएँ आती हैं जहाँ मोबाइल फोन जरूरी सूचनाओं तक किसानों की पहुँच सुनिश्चित करके उनकी आमदनी बढ़ाने में योगदान करते हैं।

प्रथम अवस्था

जब किसान यह फैसला कर रहे होते है। कि कौन सी फसल बोई जाय और मिट्टी की प्रकृति को देखते हुए किस तरह के बीज चुने जायें।

द्वितीय अवस्था

फसल की बुआई के वक्त का फैसला करते समय और बढ़ती हुई फसल की सुरक्षा के उपाय करते हुए।

तृतीय अवस्था

फसल किस मंडी में और किस कीमत पर बेचनी चाहिए, इसका फैसला करते वक्त।

सूचना तकनीक का इस्तेमाल करके गाँवों को उन्नत एवं विकसित किया जा सकता है। कृषि हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कृषि उत्पादन पर ही गाँवों की खुशहाली निर्भर करती है। ई–कृषि या ई–खेती का उपयोग भूमि की उत्पादकता एवं कृषि उत्पादन को बढ़ाने में प्रभावी भूमिका निभा सकता है। इसलिए केन्द्र सरकार की सहायता से विभिन्न राज्य सरकारों ने ई–कृषि की तरफ कदम बढ़ा दिये हैं। ई–कृषि का तात्पर्य है कृषि में सूचना–संचार तकनीक विशेषकर इन्टरनेट का उपयोग करना। इस तकनीक के जरिए

कम्प्यूटर, लैपटॉप, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन आदि की मदद से किसानों तक आवश्यक जानकारी तत्काल पहुँच जाती है। केन्द्र सरकार किसानों को ई–कृषि की जानकारी देने तथा आवश्यक उपकरण व सेवाएँ उपलब्ध कराने के प्रयास कर रही है। इसके अन्तर्गत किसानों को सूचना टेक्नोलॉजी के माध्यम से नये कृषि यन्त्रों की जानकारी देकर कृषि कार्यों में मशीनों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा चलाई जा रही वेबसाइट पर किसानों को बहुत उपयोगी जानकारी तत्काल मिल जाती है।

- वेबसाइट के माध्यम से किस फसल को कब कितनी मात्रा में पानी देना है इसकी जानकारी पल भर में किसानों तक पहुँचायी जा सकती है।
- किस फसल के लिए कौन–कौन सी खाद उपयोगी है इसकी जानकारी भी किसानों तक पहुँचायी जा सकती है।
- उपग्रह से प्राप्त मौसम सम्बन्धी सूचनाएँ भी समय पर किसानों तक पहुँचायी जा सकती है।

सूचना–संचार तकनीक का प्रयोग कर ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक योजनाएँ चलायी जा रही हैं जिनका कृषि एवं ग्रामीण विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है इसमें से कुछ प्रमुख योजनाएँ इस प्रकार है–

किसान कॉल सेंटर

सूचना एवं संचार तकनीक का प्रयोग कर हम अपने देश एवं विश्व के विकसित देशों के कृषि विश्वविद्यालय एवं कृषि वैज्ञानिकों से अपने देश एवं क्षेत्र की आवश्यकता के मुताबिक जरूरी सूचनाएं एवं जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं साथ ही किसान अपनी किसी समस्या के बारे में तत्काल उनसे बात कर सकते हैं। इसका एक प्रमुख उदाहरण है 'किसान कॉल सेंटर'। जहाँ किसान फोन करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते है। ये सेंटर किसानों को विभिन्न फसलों की देख–रेख के साथ ही मौसम आधारित बीमारियों से निबटने की जानकारी भी दे रहे हैं। किसान किस तरह से खेती के जरिए अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकता है, इस दिशा में किसान कॉल सेंटर काफी उपयोगी साबित हो रहे हैं। यहाँ किसान फोन करके अपनी हर समस्या का समाधन पा लेता है किसान कॉल सेन्टरों पर अलग–अलग विषयों के विशेषज्ञों को भी तैनात किया जा रहा है ताकि किसान के हर सवाल का सही जवाब मिल सके। किसान भूमि, सिंचाई, उर्वरक आदि के प्रयोग के बारे में किसान कॉल सेन्टर से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। देश का कोई भी किसान 1515 नम्बर पर डायल करके अपनी समस्या का हल पा सकता है। इसके लिए उसे किसी तरह के बिल का भुगतान भी नहीं करना पड़ता है। अब इसमें उत्पादन बढ़ाने के साथ–साथ उपज की बिक्री से जुड़ी जानकारी व परामर्श को भी शामिल किया जायेगा।

ई–चौपाल

यह योजना भी गाँवों की समस्याओं को हल करने के लिए तैयार की गयी है। इस सेवा का उद्देश्य किसानों को दलालों और बिचौलियों के गोरखधन्धे से मुक्त कराकर उन्हें कृषि यन्त्रों, मौसम फसल तथा कृषि सम्बन्धी अन्य जानकारी उपलब्ध कराना है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में ई–प्रशासन की अग्रणी योजना है। ई–चौपाल के सेवा केन्द्रों में एक ओर किसानों को उपयोगी जानकारी दी जाती है और दूसरी ओर उनकी समस्याओं को सुन–समझकर उनका समाधान करने का प्रयास किया जाता है।

जनमित्रा योजना

यह योजना वास्तव में एक समेकित ई–प्लेटफार्म है। इस योजना का उद्देश्य सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी गाँवों के लोगों तक सुगमता से पहुँचाने के लिए जिले के सभी विभागों और अनुभागों को लोकल एरिया नेटवर्क के जरिए जोड़ना है। इससे लोग किसी भी विभाग की जानकारी एक ही स्रोत से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इस सेवा से कम्प्यूटरीकरण के जरिए प्रशासनिक कार्यों को शीघ्र निपटाने, उनमें पारदर्शिता लाने और सूचना के अधिकार के बेहतर इस्तेमाल को सुनिश्चित करने में मदद मिल रही है। इसके अन्तर्गत ग्रामीण इन्टरनेट सामुदायिक सूचना केन्द्रों के माध्यम से लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, वाणिज्य जैसे क्षेत्रों में ई–सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं।

ज्ञानदूत योजना

सूचना तकनीक का उपयोग करके 'ज्ञानदूत' योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश जैसे जनजाति बहुल राज्य में गरीब तथा वंचित समुदायों के लोगों में आधुनिक और नई सोच विकसित की जा रही है। ज्ञानदूत गाँववासियों के लिए इंटरनेट आधारित पोर्टल है इसका उद्देश्य सूचना तकनीक के उपयोग का सस्ता और वित्तीय दृष्टि से आत्मनिर्भर मॉडल प्रस्तुत करना ताकि वे सूचना तकनीक का उपयोग करके राज्य में चल रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त कर सके। ज्ञानदूत सेवा गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से जुड़ी सुविधाएँ भी उपलब्ध कराती है। यह सेवा ऑनलाइन हिन्दी भी सिखाती है।

लोकवाणी

ग्रामीण विकास के लिए सूचना तकनीक के इस्तेमाल की यह अनूठी योजना 2004 में उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में शुरू हुई। इसका उद्देश्य गांव वालों और प्रशासकों तथा कर्मचारियों के बीच सीधा सम्पर्क कायम करना है। इस योजना में सूचना के अधिकार को भी शामिल किया गया है। यह सेवा आम लोगों को कम्प्यूटर नेटवर्क के जरिये भूमि रिकॉर्डों, निविदाओं और रोजगार के अवसरों तथा अन्य संबंधित गतिविधियों की जानकारी सुलभ कराती है। इसके साथ–साथ राशन दुकानों के लिए अनाज के आवंटन, विकास कार्यों पर खर्च तथा ग्राम सभाओं को उपलब्ध कराई गयी धनराशि आदि ब्यौरा सार्वजनिक किया जाता है।

लोकमित्रा

इस सेवा का विकास हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय सूचना केन्द्र ने किया है। इसका उद्देश्य गाँवों के लोगों को सरकारी नीतियों व कार्यक्रमों की जानकारी देना है। साथ ही यह सेवा सरकारी कार्यक्रमों में आम लोगों की भागीदारी बढ़ाने में मदद करती है इसके साथ–साथ इस सेवा के माध्यम से किसान ऑनलाइन क्रय–विक्रय भी कर सकते हैं।

आकाशगंगा

यह योजना गुजरात में डेयरी सहकारी समिति द्वारा शुरू की गयी है इसका उद्देश्य ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों को सूचना टेक्नोलॉजी के उपयोग से हिसाब–किताब, क्रय–विक्रय तथा अन्य सम्बन्धित कार्य जल्दी और पारदर्शी तरीके से पूरा करने की सुविधा उपलब्ध कराना है। यह नेटवर्क अपने एकाउटिंग साफ्टवेयर में दूध के कारोबार का विवरण भरकर समूची कार्य प्रक्रिया की जानकारी सम्बन्धित लोगों को उपलब्ध करा देता

है। आकाशगंगा योजना से गुजरात सहित 8 राज्यों के 34 जिलों के 1000 गाँवों के करीब 2 लाख ग्रामीण दुग्ध उत्पादक लाभ उठा रहे हैं।

रूरल नॉलेज सेंटर

केन्द्र सरकार की इस परियोजना को नाबार्ड के जरिए क्रियान्वित किया जा रहा है। इन केन्द्रों में आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार तकनीक के जरिए किसानों को लाभ पहुँचाया जा रहा है। यहाँ पहुँचकर किसान अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। हालांकि अभी तक ये सेंटर प्रायोगिक तौर पर खोले गये हैं, लेकिन भविष्य में इन्हें विस्तारित कर हर गाँव से जोड़ने की योजना है।

किसान चैनल योजना

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय एवं टेरेस्टरीयल नेटवर्क के सहयोग से वर्ष 2004 से किसान चैनल योजना का संचालन किया जा रहा है। इसके जरिए कृषि सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है। एक घंटे के दौरान किसानों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए जानकारी दी जाती है। इसका उद्देश्य कृषि प्रयोगशालाओं एवं अनुसंधान केन्द्रों से किसानों को जोड़ना है।

कॉमन सर्विसेज सेंटर (सामान्य सेवा केन्द्र) सीएससी

ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने एवं सूचना–संचार प्रौद्योगिकी को देश के दूरस्थ भागों तक पहुँचाने के लिए देश में एक लाख कॉमन सर्विसेज सेंटर स्थापित किए गए हैं। इसके जरिए कभी भी और कोई भी सूचना तथा सेवा उपलब्ध कराने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए देश के 6 लाख गाँवों में इंटरनेट की सुविधा प्रदान कर लाभान्वित किया जा रहा है। इससे किसानों को यह फायदा होगा कि वे कृषि आधरित बाजार भाव, मौसम अनुमान, कृषि क्रियाओं एवं नई कृषि तकनीक के बारे में जान सकेंगें, जिससे किसान परम्परागत खेती के साथ ही व्यावसायिक खेती की ओर अग्रसर होंगे। सी.एस.सी. योजना के तहत पूरे भारत में 10 लाख से अधिक ग्रामीण व्यापारों का तन्त्र बनाने में मदद मिलेगी। इन सेंटरों से ग्रामीण इलाके के शिक्षित बेरोजगारों को भी फायदा मिलेगा और शिक्षित बेरोजगारों का गाँव से पलायन रुकेगा।

इस प्रकार सूचना तकनीक का प्रयोग कर गाँवों के विकास को अत्यन्त तीव्र किया जा सकता है और इन्टरनेट के माध्यम से हमारे गाँव भी समूचे विश्व से जुड़ जायेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत की कुल जनसंख्या में से 65 प्रतिशत आबादी आज भी ग्रामीण इलाकों में रहती है। आज भारत महान् अवसरों की दहलीज पर खड़ा है, मजबूती के साथ आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था और साक्षर युवाओं की तेजी से बढ़ती जनसंख्या और प्रौद्योगिकी का व्यापक आधार इसे एक ऐसा अवसर उपलब्ध कराते हैं, जिसकी बदौलत यह एक मजबूत शक्ति के रूप में उभर रहा है। लेकिन गरीबी और असमानता को कम करने की चुनौती से भी भारत को निपटना है। दुनिया भर में यह स्वीकार किया गया है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी गरीब और अमीर के बीच के अन्तर को पाटने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारे देश ने ध्वनि संचार के क्षेत्र में फासलों को कम करने में तरक्की की है, लेकिन इंटरनेट ब्राडबैंड की पहुँच काफी कम है। इसकी मुख्य वजह वायरलाइन टेलीफोन का सीमित प्रसार और ब्राडबैंड प्रौद्योगिकी की अनुपलब्धता है।

गाँवों में ब्राडबैंड

सरकार की ओर से हर गाँव को ब्राडबैंड से जोड़ा जा रहा है। इस योजना के अमलीजामा पहनने पर सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि ग्रामीण को अपने ही गाँव में हर तरह की सुविधाएँ मिल सकेंगी तो करीब 1 करोड़ 10 लाख से अधिक बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा। इस योजना से ग्रामीण इलाके में बहुत ही व्यापक स्तर पर बदलाव नजर आने लगेगा। इसकी शुरूआत हो चुकी है। इस योजना के अमलीजामा पहनने के बाद गाँव–गाँव बीपीओ खुलेंगे और युवाओं को रोजगार के लिए शहरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इससे ग्रामीण इलाकों में बैकिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा से संबंधित सेवाओं को पहुँचाना आसान हो जाएगा। इसके तहत गाँवों को आप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा जा रहा है। यह योजना इसीलिए भी बेहद अहम है क्योंकि इसके लागू होने से गाँव के आम आदमी तक सार्वजनिक सेवाओं की पहुँच भी बहुत आसान हो जाएगी। यानी ग्रामीणों के लिए राशनकार्ड, चुनाव पहचान पत्र, बिजली, पानी का बिल, पासपोर्ट, जमीन–जायदाद से जुड़े कागजात, रेलवे टिकट, हवाई टिकट, कॉलेजों में दाखिला और बैंकों में खाता खुलवाने समेत अन्य बैंकिंग सुविधाएँ हासिल करना ज्यादा जटिल काम नहीं रहेगा। अतः इस पहल से ग्रामीण विकास को नये तरीके से गति देने की भी कोशिश की जा रही है। अब गाँवों में भी शहरों की तरह ही संचार के एक के बाद एक प्रोजेक्ट लगाये जा रहें हैं।

इन सबके बीच गाँवों में बीपीओं खोलने की योजना से काफी आशाएँ हैं। यह योजना कई स्तर पर ग्रामीण विकास को गतिशील बनाएगी। रोजगार, पारदर्शिता, उपलब्धता सहित तमाम ऐसे पहलू ग्रामीण विकास को नई ऊर्जा प्रदान करेंगे, जिसकी बदौलत भारत के गांवों और शहरों की दूरियाँ न के बराबर रह जाएगी। इसका सबसे ज्यादा फायदा यह होगा कि ग्रामीणों को छोटी–छोटी जरूरतों एवं जानकारियों के लिए इधर–उधर भटकना नहीं पड़ेगा। इस तरह देखा जाय तो यह योजना पूरी तरह से लागू होने के बाद ग्रामीण विकास को नया आयाम मिलेगा। ग्राम पंचायतों के इस योजना से जुड़ने के बाद हर ग्रामीणों एवं किसानों को विभिन्न तरह की सलाह भी मिल सकेगी। वे इंटरनेट के जरिए अपनी जरूरतों के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे। सबसे ज्यादा फायदा किसानों को मिलेगा वे कृषि सम्बन्धी जानकारी और भी बेहरत तरीके से प्राप्त कर सकेंगे।

थमेगा भ्रष्टाचार, मिलेगी ग्रामीण विकास को गति

केन्द्र सरकार की ओर से जिस गति से इस योजना को लागू करने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है, उससे कल का भारत स्वर्णिम होगा। भारत के गाँवों में अत्याधुनिक सुविधाएँ तो होंगी ही, साथ ही पारदर्शिता भी आएगी। इस तरह ग्रामीण सूचना के अधिकार को लेकर जागरूक हो रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार खुद उन्हें सूचना संचार क्रांति के बारे में जागरूक कर रही है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि ग्रामीण विकास में समय–समय पर सामने आ रही घपलेबाजी एवं भ्रष्टाचार के मामले भी थमेंगे। कोई भी अधिकारी या जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार की ओर कदम बढ़ाने की जुर्रत नहीं जुटा सकेंगे। क्योंकि उन्हें इस बात का भय होगा कि अब ग्रामीण अपने ही गाँव में स्थित केन्द्र से विकास कार्यों से लेकर सम्बन्धित कार्य के लिए जारी धन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इससे ग्रामीण विकास के नाम पर की जा रही खानापूर्ति भी थमेगी। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह

योजना ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। गाँवों में भी शहरों जैसी हाइटेक सुविधाएँ होगी और शहरी चकाचौंध नजर आएगी। बस इसके लिए जरूरत है कुछ समय इंतजार करने की।

ब्राडबैंड कनेक्शन से शैक्षिक विकास

शिक्षा के क्षेत्र में संचार संसाधनों के अधिकाधिक प्रयोग से शैक्षिक विकास एवं उसकी गुणवत्ता में व्यापक सुधार लाया जा सकता है। आज ज्यादातर स्कूलों में कम्प्यूटर की शिक्षा दी जा रही है, लेकिन ब्राडबैंड कनेक्शनों को ग्रामीण इलाके में पहुँचाने से गाँवों के विद्यालयों में भी वे सभी सुविधाएँ पहुँचायी जा सकेंगी जो आज शहरों के अच्छे स्कूलों में ही उपलब्ध हैं। इससे ग्रामीण शिक्षा की दिशा में बेहतर प्रयास हो सकेगा। जब बच्चे बचपन से ही कम्प्यूटर शिक्षा से जुड़े रहेंगे तो उनकी शैक्षिक गुणवत्ता अपने आप उच्च–स्तरीय हो जाएगी।

सूचनाओं को रफ्तार, राह हुई आसान

सूचना एवं संचार क्रान्ति ग्रामीण विकास में किस कदर कारगर है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि आज गाँव में किसी भी चीज की जरूरत हो, लोग मोबाइल से तुरन्त सम्बन्धित स्थान से अपनी जरूरत बताते हैं और वह अगले ही कुछ पलों में हाजिर हो जा रहा है। मोबाइल फोन ने गाँव के जीवन में क्वालिटी ला दी है। अब यदि परिवार के किसी सदस्य को गाँव में रहना हो तो किसी तरह की दिक्कतें नहीं आती हैं। क्योंकि मोबाइल क्रान्ति ने यह विश्वास दिला दिया है कि समस्या आते ही कुछ ही पल में उसका समाधान भी हो जायेगा। खासतौर से जो लोग रोजगार के सिलसिले में शहरों में रहते हैं और परिजन गाँव में रहते हैं तो उन्हें न तो उनकी बीमारी को लेकर चिन्ता करने की जरूरत होती है और न ही अन्य बातों को लेकर क्योंकि उन्हे पता है कि समस्या आते ही तुरन्त मोबाइल से सन्देश मिल जायेगा और वे गाँव में पहुँचकर समस्या का समाधान भी कर लेंगे। इस इस तरह मोबाइल ने शहर और गाँव की दूरी को भी कम कर दिया है। गाँवों में मोबाइल के महत्व को आशा सहयोगिनी के रूप में कार्य कर रही मंजू शर्मा बताती हैं कि पहले तो किसी प्रसूता की तबीयत खराब होती थी तो उन्हें बुलाने के लिए आना पड़ता था। इस सारी प्रक्रिया में काफी वक्त लगता था, ऐसे में प्रसूता की तबियत बिगड़ने का डर रहता था, लेकिन अब मेरा मोबाइल नंबर हर ग्रामीण महिला के पास है। ऐसे में प्रसव के समय उसे तत्काल सूचना मिल जाती है और वह प्रसूता को लेकर अस्पताल पहुँच जाती है, गाँव से अस्पताल के लिए निकलते ही वह अस्पताल भी फोन कर देती हैं। ऐसे में अस्पताल में भी सारी व्यवस्थाएँ तैयार रहती हैं। वह कहती हैं कि मोबाइल होने की वजह से ही वह कई गंभीर परिस्थितियों को भी हल कर सकी। अतः मोबाइल होने की वजह से मातृ–शिशु मृत्यु दर में गिरावट आ रही है।

प्रसारण एवं केबल क्षेत्र

संचार क्रान्ति में आई तेजी का असर प्रसारण एवं केबल क्षेत्र में भी पड़ा है। पिछले पाँच वर्षों में प्रसारण एवं केबल के बाजार की गतिशीलता में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है अब गाँव के लोग सिर्फ दूरदर्शन देखने को मबजूर नहीं है। वे भी शहरी इलाके की तरह विभिन्न चैनलों का लुत्फ उठाते हुए मनचाहा कार्यक्रम देख सकते हैं।

संचार क्रान्ति की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भूमिका

ग्रामीण स्तर पर संचार क्रान्ति का विकास होने से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में काफी सुधार आया है। ई–गवर्नेन्स के जरिए खाद्यान्न वितरण में होने वाली धांधली पर रोक लगी है। गरीबों को उनके हिस्से का अनाज आसानी से मिलने लगा है। विभिन्न राज्यों में जहाँ खाद्यान्न वितरण की प्रणाली सरल हो गयी है, वही किसी भी स्थान से अपने गांव की राशन वितरण प्रणाली के बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है। जो लोग धांधली करने की कोशिश करते हैं वे ऑनलाइन डाटा होने की वजह से पकड़े जाते हैं।

गाँवों को शहरों जैसा उन्नत व विकसित करने के लिए सूचना एवं संचार टेक्नोलॉजी के उपयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। फिलहाल एक सच्चाई यह भी है कि जिस गति से सूचना एवं संचार तकनीक का विस्तार हो रहा है, उसी गति से विकास के दूसरे पहलुओं को भी तेज करने की जरूरत महसूस की जा रही है। क्योंकि सूचना एवं संचार तकनीक सूचना तो मुहैया करा सकते हैं, लेकिन अगर उन सूचनाओं का पूरा फायदा उठाने के लिए बिजली, सिचाई और सड़क जैसे जरूरी ढाँचागत सुविधाएँ मौजूद नहीं हैं तो फिर वे सूचनाएँ बेकार हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर गाँव में सड़क नही पहुँची होती तो सिर्फ मोबाइल से वैसे बदलाव नहीं आ पाते जो इन दोनों के मेल से आए। इन सब के साथ ही साक्षरता दर का बढ़ना एक और बुनियादी जरूरत है, जो अपेक्षित बदलावों को तेजी से अमल में लाने की जरूरी शर्त है।

संदर्भ ग्रथ सूची

1. चन्द्र, उमेश, 2001 : कैसे सम्भव होगा गांवों का वास्तविक विकास, कुरूक्षेत्र, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सूचना भवन, नई दिल्ली, अंक 5, पृ0 3–5।
2. भारत, 2008 : सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृ0 467।
3. मणि, दिनेश, 2001 : ग्रामीण विकास, कल आज और कुल, कुरूक्षेत्र, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सूचना भवन, नई दिल्ली, अंक 5, दिसम्बर, पृ0 7–8।
4. मूर्ति, नारायण एन0आर0, 2007, लम्बा है रास्ता और मंजिल अभी दूर, योजना, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, योजना भवन, नई दिल्ली, अंक 5 अगस्त, पृ0 79–89।
5. श्रीवास्तव, मयंक, 2007 : ग्रामीण भारत में विकास की क्रांति का दौर, कुरूक्षेत्र, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सूचना भवन, नई दिल्ली, अंक 12, अक्टूबर, पृ0 22–26।
6. शुक्ल, ए0, 2007 : पंचायती राज की बदलती तस्वीर, कुरूक्षेत्र, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सूचना भवन, नई दिल्ली, अंक 10, अगस्त, पृ 5–8।
7. एम0 के0, तिवारी, आर0 सी0 एवं सिंह, बी0 एन0 1992 : कृषि भूगोल, प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद।
8. Misra RP, Sundram, KV. Rural Development, perspective and Approaches, Sterling Pvt. Ltd., New Delhi. 1979, 428.
9. Pal CB. Integrated Rural Area Development Planning: A case Study of Mariahu Tahsil, Jaunpur, Unpublished Ph.D. Thesis, B.H.U. Varanasi. 1984, 6-25.